फिल्म सिटी के मॉडल पर फैसला जल्द

रिपोर्ट का इंतजार

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए पीपीपी मॉडल या सरकार द्वारा निर्मित व संचालित मॉडल पर जल्द निर्णय होगा। इसके लिए कंसलटेंट अगले साल मार्च तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। फिल्म निर्माता व निर्देशकों की रुचि को देखते हुए यूपी सरकार का यह मेगा प्रोजेक्ट जल्द पटरी पर आएगा। इस बात की संभावना है कि तीसरे विकल्प के तौर पर एक इंटरनेशनल स्तर की कंपनी को बतौर डेवलपर पूरा काम दे दिया जाए।

डीपीआर में बताया जाएगा कि इस परियोजना को पीपीपी मॉडल पर लाया जाए या सरकार खुद ही इस परियोजना को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस फिल्म सिटी परियोजना पर तेजी से काम कराया जाए और यह विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से सहयोग करेगी।

फिल्म सिटी के लिए अधिकांश जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे अथारिटी के कब्जे में हैं। उसके पास 780 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए व 220 एकड़ जमीन व्यवसायिक उपयोग के लिए है।

डीपीआर आने व निवेश निर्माण माडल तय होने के बाद काम शुरू होने

फिल्म सिटी के लिए कई डेवलपर कंपनियों ने बतौर सलाहकार आवेदन किया है। कंसलटेंट चयन के लिए आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) 25 नवंबर तक मांगे गए हैं। चयन के बाद कंसल्टेंट तीन महीने में इस परियोजना की रिपोर्ट देगा।

अरुणवीर सिंह, सीईओ, यमुना एक्सप्रेसवे आथारिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह

में दिक्कत नहीं आएगी। इस बार जिन फिल्म निर्माताओं को जमीन आवंटित होगी, वह उसे आसानी से बेच नहीं पाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री सतीश महाना ने बताया कि आवंटित प्लाट पर उद्योग न लगाने पर जमीन का आवंटन रद हो जाएगा।